प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वर्ष 1967–68 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड के स्थापना-काल से लेकर वर्ष 1976–77 तक निगम में किया गया कुल पूंजी निवेश 14.69 करोड़ रुपये है तथा इस अवधि में इसमें कुल 98.87 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षक की सेवा निवृत्ति की आयु

5964. **श्री फिरंगी प्रसाद** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कालेज विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक प्रभारी की सेवा निवृत्ति की आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई हैं जबकि उनके वरिष्ठ राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारी के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 52 वर्ष तथा इसके साथ-साथ चार वर्ष सेवा बढ़ाने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों के स्तर पर लाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राष्ट्रीय कडेट कोर में प्रशिक्षण देने वाले स्थायी कर्मचारी सामान्यतः रक्षा सेवाओं से आते हैं और उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु वही है जो उनकी सेवा शर्तों में निर्धारित की गई है । इन स्थायी प्रशिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय कैडेट कोर में कुछ ऐसे अशंकालिक अफसर भी हैं जो उन स्कूलों अथवा कालेजों के होते हैं जिनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर की कम्पनियों अथवा ट्रुप गठित किए जाते हैं। ये अफसर शिक्षकों में से होते हैं और राष्ट्रीयकैडेट कोर से इनकी सेवानिवृत्ति की वतमान आयु 45 वर्ष है, जिसे 50 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि अंशकालिक अफसर 45 वर्ष की आयु अथवा 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति होंगे । राष्ट्रीय कडेट कोर की संगत नियमावली को तदनुसरा संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । राष्ट्रीय कैडेट कोर में पूर्णकालिक अफसर भी हैं जिन्हें एक समय में तीन वर्ष की सेवा वृद्धि मंजर की जाती है और वे 55 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। सारे देश में विभिन्न वर्गों की सेवा-निवृत्ति की आयु एक समान है ।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर में अंशकालिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 45 वर्ष अथवा 15 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो, को राष्ट्रीय कैडेट कोर मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निश्चित किया गया है, इस समिति के अध्यक्ष डा० जी०एस० महाजनी थे। यह महसूस किया गया कि स्कूलों अथवा कालेजों के शिक्षक 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर शिक्षण व्यवसाय में अधिक रुचि ले सकते हैं और इसके अतिरिक्त, उनमें से कुछ अपना शैक्षणिक स्तर बढ़ाकर अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकते हैं जिससे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों के लिए पयप्ति समय निकालना उनके लिए संभव न हो सकेगा ।

(ग) जी नहीं ।

शंख नदी पर पुल

5965. **श्री सारंग साय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़-रांची सड़क पर शंख नदी पर पुल तैयार हो गया है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में पुल तक पहुंच मार्ग बन गया है लेकिन बिहार में पुल तक पहुंच मार्ग अभी तक नहीं बना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मुख्य पुल और मध्य प्रदेश की ओर के पहुंच मार्ग पहले ही पूरे हो गये हैं। अब बिहार की ओर के पहूंच मार्ग का कार्य भी प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है ।

Changes in the Organisational set up of the Planning Bodies

5966. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Government considers it desirable to bring about any structural changes in the organisational set up of the Planning bodies, having regard to the avowed policy of the Government for decentralisation of power ; and

(b) if so, proposals contemplated ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b) : Planning process in the country, as is evolved, involves decisions at various levels—Central Government, State Governments, and some regional bodies. Five Year Plans are finalised after extensive discussion with all the parties concerned. However, there is need for more decentralisation and local initiative in planning. Apart from the state level sub-regional and district levels have to be adequately involved in the planning processes. The Planning Commission proposes to encourage the preparation of area plans for integrated rural development at the block level.

To assist State Governments in structuring and strengthening the planning organisations, a central scheme is in operation under which special assistance is given to the States for the recruitment of adequately qualified staff and to meet other incidental expenditure for the strengthening of planning organisation. A sum of Rs. 1·92 crores has so far been provided. More assistance, as needed, will be provided next year.

मंत्रालयों द्वारा न्यूज और फीचर ऐजेंसियों की सेवाओं का उपयोग

5967. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जो न्यूज और फीचर एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करते हैं और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं और उक्त सेवाएं किस दर पर प्राप्त की जाती हैं ;

(ख) ऐसा करने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त सेवा को आरम्भ करने अथवा उसे समर्थन देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग). सूचना मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

White Paper on S.C. and S.T.

5968. SHRI R.L. KUREEL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether Government propose to issue a detailed white paper stating its policy regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to their Social, Political and Economic uplift;

(b) the date by which Government propose to advise the Committee of the M.Ps. of both the Houses dealing with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(c) whether any schemes have been formulated and being implemented to advance the economic well being of the S.C./S.T. in persuance of constitutional obligations in respect of these communities, if so, the details there of ?